

**बूंदी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक
समाज में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी मिलकर कार्य करें, युवाओं को बचाना
हम सबकी जिम्मेदारी—राज्यपाल**

टीबी मुक्त बूंदी बनाने और विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्देश

जयपुर/बूंदी, 29 जुलाई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनहित के कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 'नशामुक्त भारत अभियान' और 'राष्ट्रीय क्षय (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम' को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही, शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।

राज्यपाल श्री बागडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने नशामुक्त भारत अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले सरकारी विभागों से ही होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी मादक पदार्थों का सेवन न करें, ताकि वे आमजन के लिए एक आदर्श और प्रेरणास्त्रोत बन सकें। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि महाविद्यालयों और स्कूलों में शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखें। विद्यालयों में नियमित रचनात्मक गतिविधियां आयोजित हों, जिससे विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास हो सके।

राज्यपाल ने कहा कि युवा हमारे देश की असली ताकत हैं और इन्हें नशे के चंगुल से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षण संस्थानों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर समाज में फैल रही नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह मुहिम केवल स्कूलों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो। आमजन की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए और इस नशामुक्त समाज के निर्माण में नारी शक्ति का भी पूरा सहयोग लिया जाए।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि टीबी मरीजों की पहचान जल्द से जल्द की जाए ताकि उनका तुरंत उपचार शुरू हो सके। टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को टीबी मुक्त बूंदी के लक्ष्य के साथ काम करने का आह्वान किया। डोर-टू-डोर सर्वे और स्क्रीनिंग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि समय पर इलाज से कई जानें बचाई जा सकती हैं। मरीजों के संपूर्ण उपचार के लिए मुफ्त दवा के साथ-साथ शैक्षणिक मित्र बनकर उन्हें नियमित पोषण किट भी उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में राज्यपाल ने नल जल कार्यक्रम की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।





